THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Dasgupta, will you please be brief? I cannot allow you to speak like this.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, I have to run.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then, you please run.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Then, you please run.

DR. BIPLAB DASGUPTA: In the whole world, I have never come across an election being conducted in such a manner where the election Commission decides from where the candidates should address the public meetings ....(*Interruptions*).... It is absurd. It cannot be done. Similarly, the Election Commission proposes that by November, all the States must print the identity cards. It is something which can never be conformed to. It is not possible. I would like to suggest to the Government to look into these two things because these are things of public importance.

Mass Agitation in Hill Areas in Uttar Praedesh

उपसभापति: राजनाथ सिंह जी आपका स्पेशल मेंशन तो यहां हो चुका है।

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): आंदोलन से एक नया आयाम जुड़ गया है इसलिए दो मिनट का टाइम लूंगा।

हमारे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधी आरक्षण के विषय को लेकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र इस समय व्यथित भी हैं और आंदोलित भी हैं निस्संदेह यह मामला जहां पर संवेदनशील है वहां पर यह ज्वलंत भी है। पड़ोसी जनपदों में भी आंदोलन तेजी के साथ फैल रहा है। इस आंदोलन के साथ जो एक नया आयाम जुड़ गया है वह इस क्षेत्र में रहने वाले राज्य कर्मचारियों के आंदोलन में शरीक होने के कारण इस आंदोलन को एक नया आयाम मिला है। किस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को आहत हुई है इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देहरादून में 500 नागरिकों ने अपने जिस्म के खून से हस्ताक्षर करके महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जिस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था पर्वतीय क्षेत्र में की गई है इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे मेरीटोरियस स्टुडेंट्स को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल रहा है। यह व्यवस्था कम से कम पर्वतीय क्षेत्र में समाप्त की जानी चाहिए। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है हमारी पार्टी मानती है कि आरक्षण की आज एक सामाजिक आवश्यकता है। आरक्षण को संवैधानिक और कानूनी माण्यता भी मिली है। इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को और हमारी भारत सरकार को इस मामले को जितनी गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए यह सरकार नहीं ले रही है। उलटे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक ऐसा भडकाउ बयान जारी कर दिया कि यदि हम चाहें उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में.....

उपसभापति: यह बात हो चुकी है। इस हाउस में इस बात को बार-बार नहीं कहिये।

श्री राजनाथ सिंह: सरकार में एक दल जिसकी भागदारी है उस दल के नेताओं ने कहा है इस आंदोलन में जो लोग शरीक हैं यदि उन्हें देशद्रोही कहा जाए तो यह अतिश्योक्ति नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इस आंदोलन को शांत करने के लिए संयम से काम लेना चाहिए।

उपसभापति: आपने दो मिनट मांगे थे, दो मिनट दे दिये।

श्री राजनाथ सिंह: व्यापार में बने रहने वाले लोग बराबर अपने बयानों के द्वारा .... (**व्यवधान**)

उपसभापति: आपका हो गया, आप बैठ जाइये।

श्री राजनाथ सिंह: ज्यादा न कहते हुए इतना निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार के प्रधान मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करने वाले हैं, ऐसी जानकारी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है। आंदोलन क्योंकि तेजी से बढ़ता जा रहा है इसलिए शीघ्रतिशीघ्र उन्हें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

उपसभापति: माथुर जी संक्षेप में बोलिए, बहुत लेट हो गये हैं।

Appointment of wage Board for Journalists

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं पत्रकारों के लिए और समाचारपत्रों में काम करने वाले अन्यों के लिए शीघ्रातिशीघ्र वेज बोर्ड अपाएंट करने की मांग को दोहराना चाहता हूं। 1992 की अगस्त में इस मांग को स्वीकार किया गया था। 1993 की फरवरी में केबिनेट ने इसको स्वीकार किया था। केबिनेट के डिसीजन के बाद घोषणा सरकार बारबार करती रही लेकिन अभी भी